THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c) The Government had approved a scheme for the allotment of plots to all the 712 persons declared eligible. Over and above the land already made available to the DDA for the purpose, additional land to cover all persons has been located in and around Chittaranjan Park. No Plam as such for allotment of plots was approved by the Government.

Strengthening of T.V. network in Punjab

2163. SHRI PA WAN KUMAR BANSAL; Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Jalandhar Doordarshan programmes are not received at Chandigarh and Bhatinda; and on

(b) if so, what steps are being ta ken to strengthen the local Television Network in Punjab?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI AJIT PANJA): (a) Yes, Sir.

(b) A separate 100 W TV transmitter is envisaged to be set up under the Seventh Plan at Kasauti with a directional antenna pointing towards the Union Territory of Chandigarh. This transmitter is planned to relay programmes, *inter alia,* to be received off air from Doordarshan Kendra, Jalandhar. Secondly, programme generation facility is envisaged to be set up at Chandigarh for production of TV programmes of local interest.

As regards Bhatinda, the 10 KW high power transmitter there is envisaged to be linked with the Jalandhar Doordarshan by mircowave circuit by establishment by Deptt. of Telecommunication of an end-link at Bhatinda, to enable, *inter alia,* relay of Jalandhar programmes from Bhatinda.

In addition, schemes have been included in the VII Plan of Doordarshan for establishment of a low power (100W) TV Transmitter at Gur-| daspur and a transposer at Talwara.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना

2164. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों को किन-किन प्रयोजनों के लिये वित्तीय सहायता देती है ;

(ख) क्या इस आवंटन के साथ यह शर्त भी रखी जाती है कि इस धनराशि को किसी प्रयोजन विशेष के लिए खर्च किया जाए ;

(ग) क्या इस विषय में कोई मूल्यांकन किया गया है ; यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और यदि अभी तक कोई मल्यांकन नहीं किया गया है तो यह कब तक किये जाने की संभावना है ; और

(घ) कौन-कौन से कृषि विश्वविद्यालयों अथवा महाविद्यालयों ने इस आबंटित धनराशि को खर्च किया ; और इस संबंध में बिहार की क्या स्थिति है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् निम्नलिखित कार्यों के लिए राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है :—

1. कृषि विकास के लिए राज्यों के वैज्ञानिक/तकनीकी श्रमशक्ति की जरूरतों

को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले शैक्षिक/प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तैयार करना, उसका विस्तार तथा विकास करना ।

2. उनकी क्षेत्रीय अनुसंधान क्षमताओं को सुदृढ़ करना ।

3. अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं और तदर्थ अनुसंधान प्रायोजनाओं के अनुसंधान कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना ।

4. विस्तार शिक्षा क्रियाकलापों को कार्यान्वित करना ?

(ख) जी हां, श्रीमन् ।

(ग) निहित प्रक्रियाओं के द्वारा उपरोक्त प्रायोजनाओं के कार्यन्वयन की प्रगति का नियमित रूप से प्रबोधन करना । ये प्रायोजनाएं बहुत हद तक अपने उद्देश्यों में सफल रही हैं।

(घ) बिहार के दो विश्वविद्यालयों सहित सभी 26 राज्य कृषि विश्वविद्यालय निहित (दी गई) प्रक्रिया के अनुसार आवंटित धन खर्च कर रहे हैं।

दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ियां

2165. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं, इनमें कहां-कहां बिजली, पानी और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हैं ; तथा जिन झग्गी-झोंपड़ियों में ये सुविधाएं नहीं हैं वहां ऐसी सुविधायें दिए जाने की क्या व्यवस्था की जा रही हैं ; और

(ख) ऐसी कालोनियों में से कितनी नियमित कर दी गई हैं और वहां पर बिजली और जल-पूर्ति तथा नालियों की क्या स्थिति है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बाढ़ और सूखे की स्थिति में सहकारी समितियों की भूमिका

2166. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर की विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा बाढ़ और सूखे की वर्तमान स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या भूमिका निभाई जा रही है ;

(ख) बिहार की सहकारी समितियां इस दिशा में क्या कार्य करने का विचार रखती है ; और क्या केन्द्र सरकार भी इसमें कोई सहयोग दे रही हैं तथा इस संबंध में किये गये कार्यों का मूल्यांकन करने के लिये कोई व्यवस्था की गई है ; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की और क्या-क्या योजनायें हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (ग) बाढ़ और सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये बिहार सहित सभी राज्यों में सहकारी बैंक प्रभावित किसानों को दूसरी बुवाई या चारे सहित वैकल्पिक फसलें उगाने के लिये नये सिरे से धन पेशगी देने के वास्ते राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से अतिरिक्त पुनर्वित्त की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं । सहकारी बैंकों द्वारा भिन्न-भिन्न मामलों के आधार पर निवेश ऋणों को पुनर्निधारित करने के लिये नाबार्ड ने अदायगी को फिर से निश्चित करने की सुविधायें देने का वचन भी